



अधिकतम : 24° C

न्यूनतम : 12° C

खबरें सुपाता नहीं, छापता है

शाह टाइम्स

देहरादून, सोमवार 24 नवम्बर 2025 देहरादून संस्करण: वर्ष 25 अंक 107 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00

shahtimes2015@gmail.com

मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 4 विक्रमी सम्वत् 2082

2 जमादियल उखरा 1447 हिजरी

नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वानी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित

**बीएलओ की मौत के आंकड़े वास्तविकता से बहुत अधिक, स्थिति अत्यंत चिंताजनक: खड़गे**

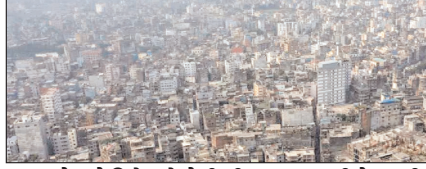
पेज 2

**केएल राहुल साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में कप्तानी करेंगे**

खेल टाइम्स

**सेना बनाम सर्वोच्च न्यायालय बनाम मानवाधिकार**

समादकीय

**बांग्लादेश में विशेषज्ञों ने टी भीषण भूकंप की चेतावनी**

पेज 12

संक्षिप्त समाचार

एसआईआर अभियान: 19 दिन में 6 राज्यों में 15 बीएलओ की मौत नई दिल्ली

देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेसिव रिविजन (एसआईआर) अभियान के बीच बुध लेवल अफसरों (बीएलओ) की मौतों चिंता का कारण बन गई हैं। 21 नवम्बर की रात से 22 नवम्बर के मध्य प्रदेश में दो बीएलओ की बीमारी के कारण मौत हो गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में दो बीएलओ की हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल में एक महिला बीएलओ ने भी आत्महत्या कर ली। मृतकों के परिजनों ने ज्यादा काम और लक्ष्य पूरा करने के दबाव को मौत का कारण बताया है। निर्वाचन आयोग की शनिवार की रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में राजस्थान में सर्वाधिक 60.54 फीसदी फॉर्म डिजिटलाइज हुए हैं। वहीं, केरल में सबसे कम 10.58 फीसदी फॉर्म डिजिटल हो पाए हैं। कुल 98.98 फीसदी फॉर्म बंद चुके हैं।

मैदानों में कड़ाके की सर्दी शुरू, चार शहरों में एक्वआई 300+

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी हो रही है। इससे मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर समेत 7 शहरों में शनिवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। पंचमढ़ी में सबसे कम 6.2 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान में सर्दी के साथ धुंध का असर बढ़ने लगा है। इसके कारण शहरों में प्रदूषण भी बढ़ गया है। शनिवार शाम को बिवाड़ी, जयपुर, कोटा, टोंक में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्वआई) लेवल 300 से ऊपर दर्ज हुआ। 8 शहरों में एक्वआई 200 से ऊपर रहा। यूपी और बिहार में अब तक सर्दी से राहत थी, लेकिन सोमवार से तापमान गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, यूपी में पहाड़ों से ठंडी हवाएं आने लगी हैं। इसके कारण, अगले पांच दिनों के दौरान राज्य का तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिरने की आशंका है। बिहार में 24 नवम्बर के बाद तापमान गिरने लगा है। 27-28 नवम्बर तक भीषण सर्दी पड़ सकती है। कई शहरों में अभी से घना कोहर छाने लगा है।

शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ से संबंधित विधेयक नहीं आएगा: गृह मंत्रालय

नई दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की वैधानिक स्थिति बदलने के बारे में आ रही रिपोर्टों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अभी चंडीगढ़ के लिए केंद्र द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को पास विचाराधीन है और इस संबंध में संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इन रिपोर्टों के कारण सियासी हलकों में तीखी प्रक्रिया हो रही है। इसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को परिवर्तित करने के बारे में कोई बातचीत नहीं चल रही है। पोस्ट में कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

देश में एक दिसम्बर से केस लिस्टिंग का नया सिस्टम: जस्टिस सूर्यकांत

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट के 53वें सीजेआई के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले संकेत दिए कि वे एक दिसम्बर को देश को सरप्राइज देंगे। उन्होंने केवल इतना इशारा किया कि सरप्राइज केंसों की लिस्टिंग को लेकर है। लिस्टिंग की व्यवस्था इतनी अच्छी होगी कि सब इसका स्वागत करेंगे।

देश के सबसे बड़े ज्यूडिशियल ऑफिस का चार्ज संभालने से पहले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डेविड रेड, जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि उनका मेन फोकस देश की अदालतों में पेंडिंग केसों की भारी संख्या को कम करना होगा। जस्टिस सूर्यकांत

- बोले - मेरा फोकस अदालतों में पेंडिंग केसों की संख्या कम करना, आज शपथ ग्रहण
- जस्टिस सूर्यकांत एक दिसम्बर को देश को सरप्राइज देंगे
- लिस्टिंग की व्यवस्था इतनी अच्छी होगी सब इसका करेंगे स्वागत

सुप्रीम कोर्ट के उन मामलों का निपटारा करेंगे, जो हाईकोर्ट में लास्ट स्टेज में हैं और सुप्रीम कोर्ट में लॉबित होने के कारण लटक हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने मीडिएशन को भी एक गेम चेंजर बताया। उन्होंने कहा कि यह लिटिगेंट्स को कोर्ट के बाहर तेजी से सेटलमेंट दिला सकता है। अगर पेंडिंग और प्री-लिटिगेशन केस मीडिएशन से

सुलझाए जाते हैं, तो कोर्ट पर बोझ काफी कम हो जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर लीगल जर्नलिस्ट्स के एक ग्रुप को एड्रेस कर रहे थे। जस्टिस सूर्यकांत की बकटलिस्ट के अनुसार एरियर (पेंडिंग केस) को इंडिविजुअल कोर्ट लेवल पर और पैन-इंडिया बेसिस पर, दोनों तरह से एड्रेस

किया जाना चाहिए। एक बड़ा चैलेंज मामलों का ओवरलैप होना है। कई जरूरी केस 5, 7 या 9 जजों की कॉन्स्टीट्यूशनल बेंच को भेजे गए हैं और इस वजह से, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कई दूसरे केस नहीं देख पा रहे हैं। हजारों मामले इन बड़ी बेंचों के फैसलों का इंतजार करते हुए रुके हुए हैं। इस वजह से, हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट

कोर्ट भी कई कानूनी सवालों की वजह से अटक हुए हैं, जो अभी तक सुलझे नहीं हैं। हालात को करीब से समझने के लिए लगभग एक हफ्ते का समय लगेगा और इस काम में भी कुछ समय लगेगा। एक क्राइटेरिया यह है कि सबसे पुराने केस पहले लिए जाएं। हालांकि, कुछ नए मामले भी हैं जिन पर तुरंत और सच में ध्यान देने की जरूरत है। डिजिटल कोर्ट और एआई के इस्तेमाल को भी ज्यूडिशियल सिस्टम के कामकाज में शामिल किया जा सकता है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जो मतलब का बदलाव ला सकती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हर लिटिगेंट आखिरी फैसला सुनाने के लिए एक इंसानी कोर्ट की उम्मीद करता है। इसलिए, मुकदमेबाजी में एआई की सीमित लेकिन उपयोगी भूमिका है।

शीर्ष उल्फा कमांडर, बाँडी गार्ड ने किया सरेंडर गुवाहाटी

यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के एंटी-टॉक ग्रुप के एक शीर्ष कमांडर और उसके एक साथी ने रविवार को असम राइफलस के सामने सरेंडर कर दिया। अरुणोर्षो दहोतिया उर्फ बिजित गोर्गोई नाम का यह कमांडर, संगठन की 709 कंपनी से जुड़ा था, जिस उल्फा (इंडिपेंडेंट) के नाम से भी जाना जाता था। दहोतिया को उल्फा (आई) चीफ परेश बरुआ का भरोसेमंद साथी भी माना जाता है। दहोतिया के साथ उसके एक बाँडी गार्ड, फ्रांसिस असोम ने भी आत्मसमर्पण कर दिया।

एआई के गलत इस्तेमाल पर रोक जरूरी: पीएम मोदी

पर रोक जरूरी: पीएम मोदी

कहा: अपराध और आतंकवाद में एआई का प्रयोग खतरनाक

जोहान्सबर्ग, वार्ता



पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में हो रहे जी-20 समिट के दौरान दुनिया के 20 ग्लोबल लीडर्स से मुलाकात की। इनमें इटली की प्रधानमंत्री जोर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों समेत कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेता शामिल रहे। मोदी ने रविवार को समिट के तीसरे सेशन में दुनिया को एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए सभी देशों को मिलकर इसके लिए मजबूत नियम-कानून बनाने चाहिए। मोदी ने कहा कि एआई पर एक ग्लोबल कांफ्रेंस (यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौता) होना जरूरी है। इसमें तीन चीजें सबसे जरूरी होंगी। निगरानी, सुरक्षा और पारदर्शिता। उन्होंने खास तौर पर चेतावनी दी कि डीपफेक वीडियो-ऑडियो, अपराध और आतंकवाद में एआई का इस्तेमाल बहुत खतरनाक है। इसलिए समय रहते पूरी दुनिया को एकजुट होकर कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पहले मोदी ने बताया था कि, शनिवार को जी-20 शिखर सम्मेलन की बैठक अच्छी रही। उन्होंने कहा कि मैंने दो सत्रों में भाग लिया और प्रमुख मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। मोदी

जोहान्सबर्ग। साउथ अफ्रीका में 20वां जी-20 समिट रविवार को बिना औपचारिक हैडओवर के समाप्त हो गया। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किसी अमेरिकी अधिकारी को गवेल अध्यक्षता का प्रतीक हथौड़ा नहीं सौंपा। विदेश मंत्री रोनल्ड लामोला ने कहा कि आज कोई औपचारिक हैडओवर सरेमनी नहीं होगी। अमेरिका चाहे तो सोमवार से डीआईआरसीओ (दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय) के दफ्तर से जी-20 से जुड़े दस्तावेज ले सकता है। इसके बाद व्हाइट हाउस की डिप्टी सेक्रेटरी अन्ना कैली ने आरोप लगाया कि साउथ अफ्रीका ने जी-20 का औपचारिक हैडओवर नहीं कर गलत किया है।

ने एक्स पर बताया कि जोहान्सबर्ग में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति रामफोसा के साथ शानदार बैठक हुई। हमने भारत-दक्षिण अफ्रीका साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की, विशेष रूप से ट्रेड, कल्चर, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, एआई, रेंजर अर्थ मेटल में सहयोग में विविधता लाने पर। इसके साथ ही मोदी ने जी-20 की सफल

ट्रम्प के न आने से नाराज था साउथ अफ्रीका, अमेरिका बोला: यह ठीक नहीं किया साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने रविवार को जी-20 समिट के समापन का ऐलान किया। दरअसल, हर जी-20 समिट में पिछले साल की मेजबानी करने वाला देश, अगले मेजबानी करने वाले देश को औपचारिक रूप से 'गवेल' सौंपता है। यह एक लाइव सरेमनी होती है, जिसमें दोनों देशों के नेता आमने-सामने मौजूद रहते हैं। इस बार अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति ट्रम्प शामिल नहीं हुए। ट्रम्प ने कहा कि साउथ अफ्रीका में गैरे ईसाइयों को मारा जा रहा है।

अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति रामफोसा को बधाई दी। मोदी जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) नेताओं की बैठक में शामिल-शेष पृष्ठ दो पर

दिल्ली ब्लास्ट: उमर को जमात से मिले थे 40 लाख

नई दिल्ली। दिल्ली में 10 नवम्बर को हुए कार ब्लास्ट में शामिल सुसाइड बॉम्बर डा. उमर और डा. मुजम्मिल के बीच 40 लाख रुपये को लेकर झगड़ा हुआ था। फाँटिंग जमात की तरफ से हुई थी। इसी पैसे से सामान खरीदने में हुए खर्च को लेकर उमर और मुजम्मिल की बीच तनाव था।

एनआई टीम यूनिवर्सिटी के पास की मस्जिद के मॉलवी इश्तियाक को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसे ही जमात के जरिए कई लाख रुपये मिले थे, जिसका इस्तेमाल मुजम्मिल ने ब्लास्ट के लिए सामान खरीदने में किया था। सुत्रों के मुताबिक इन्हीं पैसों में हेरफेर को लेकर मुजम्मिल और उमर के बीच तनाव था। इधर, फरीदाबाद में पुलिस ने धौज गांव समेत 4 थाना क्षेत्रों में शनिवार को सर्वे अभियान चलाया। पुलिस टीम

- हिसाब गड़बड़ हुआ तो उमर व मुजम्मिल झगड़े
- पुलिस ने फरीदाबाद में मस्जिद, घर, होटल, गोदाम खंगाले

ने दिनभर मस्जिदों, दुकानों, होटलों, घरों व गोदामों में चेंकिंग की। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया माँड्यूल का हर आरोपी एक अलग हैंडलर को रिपोर्ट कर रहा था। मुजम्मिल का हैंडलर अलग था, जबकि ब्लास्ट करने वाला उमर दूसरे हैंडलर को रिपोर्ट कर रहा था। दो खास हैंडलर मंसूर और हाशिम एक सीनियर हैंडलर इब्राहिम के अंडर काम कर रहे थे, जो माँड्यूल को पूरी एक्टिविटीज को सुपरवाइज कर रहा था।

पाकिस्तानी पत्रकार ने फेक न्यूज फैलाई: फ्रांसीसी नौसेना हमने राफेल गिरने की बात नहीं मानी, गलत तरीके से पेश किया अफसर का बयान

पेरिस। फ्रांसीसी ने ऑपरेशन सिंदूर में राफेल गिरने की पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मोर की रिपोर्ट को फर्जी बता दिया है। नौसेना ने कहा है कि राफेल गिरने की बात न तो कभी मानी गई और न ही किसी अधिकारी ने ऐसा बयान दिया।

हामिद मोर ने एक फ्रांसीसी अधिकारी के बयान का हवाला देते राफेल गिरने का दावा किया था। फ्रांसीसी नेवी ने बताया कि रिपोर्ट में जिस अफसर का नाम लिखा गया है, वह भी गलत है। रिपोर्ट में जैक्स लीने कहा गया, जबकि सही नाम कैप्टन यवन लीने है। नेवी ने कहा कि कैप्टन लीने के पद और जिम्मेदारियों को भी बड़ा-चढ़ाकर बताया गया। फ्रांस के मुताबिक कैप्टन लीने ने न तो राफेल गिराए जाने की कोई बात कही और न ही भारत-पाकिस्तान झड़प को लेकर कोई दावा किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछे जाने पर सिर्फ इतना कहा था कि वे इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके

- हामिद मोर ने एक फ्रांसीसी अधिकारी के बयान का हवाला देते हुए राफेल गिरने का किया था दावा
- रिपोर्ट में जिस अफसर का नाम लिखा गया है, वह भी गलत : फ्रांसीसी नेवी

बावजूद रिपोर्ट में इसे पुष्टि की तरह पेश किया गया। हामिद मोर ने अपनी रिपोर्ट में कैप्टन लै. नि. के बयान का झूठा हवाला देते हुए भारत के राफेल फाइटर जेट गिरने की बात की। हामिद के मुताबिक कैप्टन लै. नि. ने कहा कि राफेल के गिरना चीन के जे-10 से, न तो तकनीकी क्षमता की वजह से नहीं, बल्कि ऑपरेशन को संभालने के तरीके वजह से हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन लै. नि. ने कहा कि राफेल में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं किया गया।



राफेल किसी भी स्थिति में जे-10 से को हरा सकता है। पाकिस्तानी पत्रकार ने कैप्टन लीने के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया कि दोनों देशों के 140+ फाइटर जेट एक-दूसरे के सामने थे। इतनी बड़ी संख्या में टारगेट होने से किसी भी विमान को मार गिराना आसान था। पाकिस्तान इस जटिल स्थिति को बेहतर तरीके से संभालने में कामयाब रहा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि पाकिस्तान का मिस इन्फॉर्मेशन नेटवर्क एक बार फिर बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा कि हामिद

मोर की रिपोर्ट में राफेल जेट्स को लेकर वही पुराने, मनगढ़ंत दावे दोहराए गए, जिन्हें अब फ्रांसीसी नेवी ने भी झूठा बता दिया है। मालवीय ने यह भी आरोप लगाया कि हामिद मोर के कुछ भारतीय मीडिया संस्थानों से करीबी संबंध हैं, जिससे पाकिस्तान की प्रोपेगंडा मशीनरी को बढ़ावा मिलता है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की लड़ाई (ऑपरेशन सिंदूर) में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी मिली थी। इस रिपोर्ट में पहलूगाम अटैक को भी आतंकी हमला न मानकर विद्रोही हमला माना गया है। 800 पनौ की इस रिपोर्ट को यूएस-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन (यूएससीसी) ने जारी किया है। रिपोर्ट पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिकी संसद में पेश हुई इस रिपोर्ट ने भारत के साथ हुई सैन्य टकराव में पाकिस्तान की जीत पर हुर्राना दी है।

वैधानिक सूचना

सीएम ने लक्ष्य सेन को खिताब जीतने पर दी बधाई

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह भाभी ने फोन पर बधाई कर वैदमंडलन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 खिताब जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य सेन को यह शानदार उपलब्धि उत्तराखण्ड ही नहीं, सम्पूर्ण देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य की मेहनत, समर्पण और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारे सभी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है और यह साबित करता है कि लगन, अनुशासन और कड़ी मेहनत के साथ हर कठिन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य सेन के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आशा व्यक्त की कि वे आगे भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और देशभक्त उत्तराखण्ड का नाम इसी प्रकार रोशन करते रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किया प्रतिभाग

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह भाभी ने रविवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के तहत उत्तराखण्ड पविलियन में उत्तराखण्ड विदेश समारोह एवं इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में वक्ता बख्त अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर नटशास्त्रा थियेटर में उत्तराखण्ड के लोक कलाकारों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। इस वृद्ध व्यापार मेले की थीम 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' रखी गयी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हमारी संस्कृति, इतिहास, प्रकृति और समृद्ध विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रतीतिष्ठ करने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ नहीं इस मेले में आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से हमारी लोक संस्कृति और उत्तराखण्ड परंपराओं की जीवंत झलक देखने को मिलती है।

शाह टाइम्स प्रमुख संवाददाता देहरादून। उत्तराखण्ड की रहानी व इल्मी शख्सियत शहर काजी व जमीअत उलमा-ए-हिन्द उत्तराखण्ड के प्रदेश उपाध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी को रविवार दोपहर नम आंखों के साथ सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। शनिवार देर शाम 75 वर्ष की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था।

रविवार सुबह ठीक 9 बजे मौलाना कासमी का भंडारी बाग स्थित आवास से अंतिम दर्शन के लिए जामा मस्जिद, पलटन बाजार लाया गया। मस्जिद के भीतर और बाहर दूर-दूर तक जनसमूह की कतारें नजर आईं। बुजुर्ग, नौजवान हर वर्ग से लोग उनके अंतिम दीदार के लिए पहुँचे। मस्जिद के आसपास की गलियाँ जामा इंसानी सैन्य से भर गईं।

सुबह 11 बजे उनकी नमाज-ए-जनाजा दारुल उलूम देवबंद के उत्तराद, मुफ्ती रियाजत कासमी साहब ने अदा कराई। जनाजे में शिरकत करने वालों की लड़ाव इतनी ज्यादा थी कि पलटन बाजार से लेकर गांधी रोड, तहसील चौक तक सड़कें और गलियाँ भी पूरी पलटन बाजार से उनका जनाजा तहसील बाजार, तहसील चौक, गांधी रोड, इनामूला बिल्डिंग, गिंस चौक से होकर चंद नगर कब्रिस्तान पहुँचा। जनाजे की कंधा देने के लिए शहीद लोरी रही। हर कोई शहर काजी को कंधा देकर सजब (पुष्प) पा चीना चलाता था।

अंतिम यात्रा में यह रहे मौजूद नमाज के बाद जनाजा जुलूस को पलटन बाजार से चंद नगर कब्रिस्तान ले जाता गया, जहाँ मौलाना कासमी को नम आंखों के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया। शहर काजी की तदपोती में शहर मुफ्ती सलीम अहमद कासमी, जमीअत के प्रदेश महासचिव

हिन्दू-मुस्लिम सभी वर्गों ने दी अंतिम विदाई

मौलाना कासमी के जनाजे में सभी धर्मी और वर्गों के लोग शामिल हुए। हिन्दू समाज के कई गणमान्य लोग और संगठनों के प्रतिनिधि भी जनाजे में मौजूद रहे, जो इस बात का प्रमाण है कि मौलाना कासमी ने अपने जीवन में ईमानदारी, सद्भाव और भाईचारे का जो पैगाम दिया, उसमें हर दिल को छुआ था। उनकी अदम्य लोकप्रियता और ईज्जत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पलटन बाजार, तहसील चौक, गांधी रोड सहित तमाम बाजार नमाज-ए-जनाजा तक पूरी तरह बंद रहे।

मौलाना शराफत अली कासमी, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सुर्यकांत धम्मना, सरदार अमर जौन सिंह, महानगर अध्यक्ष जसविंदर गोपी, कालिका मंदिर समीति के सदस्य, कालू भगत, जमीअत के प्रदेश उपाध्यक्ष मुफ्ती रईस अहमद कासमी, देहात काजी मौलाना रिसालुद्दीन हकनारी,

मुफ्ती नाजिम अशरफ, मौलाना अब्दुल मन्नान कासमी, अब्दुल सत्तार, मुफ्ती अयाज अहमद, हाफिज मोहम्मद शाहनगर, मुफ्ती ताहिर कासमी, मुफ्ती वासिल कासमी, मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती रामपुर कासमी, मदरसा बोर्ड के पुर्व उपाध्यक्ष गुलजार अहमद, हाजी सुलेमान अंसारी, मौलाना अब्बास कासमी, मौलाना अब्दुल कादिर, मुफ्ती हुज्जा कासमी, मौलाना आगिर कासमी, मुस्लिम सेवा समिति के अध्यक्ष नदीम कुरेशी, आकिब कुरेशी, इलाअत खान, ताहिर अली, जामा मस्जिद पलटन बाजार के अध्यक्ष नसीम अहमद, सचिव वसीम अहमद समेत बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की।



आजादी के बाद से देहरादून के तीसरे शहर काजी थे मौलाना कासमी

मोहम्मद शाह नजर देहरादून। शहर काजी हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी साहिब का कौनसे एक ऐसे शहर का जीवन था जिसमें शहर, समाज और देश, तीनों की सेवा को अपना फर्ज समझकर जीया। वर्ष 1981 में मजबूत 31 साल की आयु में मौलाना कासमी ने जामा मस्जिद पलटन बाजार के इमाम और शहर

■ 31 वर्ष की आयु में जनवरी 1981 में पलटनी श्री जिम्मेदारी ■ साइकिल से आते थे मस्जिद

काजी की बड़ी जिम्मेदारी को संभाला था, तब से लगातार 44 साल तक शहर काजी के तौर पर मौलाना कासमी ने देहरादून के मुसलमानों की रजतुमार्ग की। मस्जिद के अध्यक्ष नसीम अहमद ने बताया कि बादशाह ओरोजख

सबके प्यारे थे शहर काजी: हरीश रावत

देहरादून (शाह टाइम्स)। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि जो अच्छे लोग होते हैं, ईश्वर/अल्लाह उन्हें बहुत प्यार करता है। ऐसे ही सबके प्यारे थे देहरादून के शहर काजी हजरत कासमी साहब। अपनी धार्मिक निष्ठा के साथ-साथ वे सामाजिक समन्वय और समावेशिता के प्रतीक थे। उनका ज्ञान बहुत खलेगा। उनके निधन की खबर ने मुझे झकझोर दिया, हृदय अत्यंत दुखी है। अल्लाह, उन्हें अपने पास उच्च स्थान दे और उनके परिवारों को इस बड़े दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

शहर काजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कांग्रेसी



देहरादून (शाह टाइम्स)। महानगर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी की ब्रह्मा सुमन अर्पित करने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धम्मना पार्टी पदाधिकारियों के साथ पहुंचे। शहर काजी को प्रदेश कांग्रेस की ओर से ब्रह्मा सुमन अर्पित किए हुए धम्मना ने कहा कि शहर काजी साहब एक बेहतरीन खुरा मिजाज व अमन सरदे धार्मिक नेता थे और हमेशा शहर में अमन चीन और आपसी धार्मिक सीढ़ार के पक्षधर रहे। धम्मना के साथ कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉ. जयवर्धन सिंह गोपी, अभिनव धार, पार्षद अद्वैत खान, पार्षद आरुण गुप्ता, कमर सिद्दीकी, दिनेश कोशल, शहजाद, कारक व यामिन खान और साथ रहे।

उनकी सादगी व अखलाक को हमेशा याद रखा जाएगा: तौता देहरादून (शाह टाइम्स)। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योती रौतल ने कहा कि देहरादून शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी साहिब के इंतकाल को खबर बड़े दुःख के साथ प्राप्त हुई।

उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन इत्य, ईसाफ, अमन और मोहब्बत की विध्वस्त में लगा दिया। उनकी सादगी, उच्च अखलाक और सज्जन को जोड़ने वाली सोच को हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह तआला उनसे रत्नांद हो, उनको माफ़िगत फरमाए और वनतुल फिदवी में बूलंद मुकाम अता करे।

कैसे समय से ही इस मस्जिद के शाही मस्जिद का दर्जा प्राप्त है, आजादी के बाद पहले मौलाना मोमिन और फिर जौनख अल्लुख शहर काजी रहे। 1981 से मौलाना कासमी ने देहरादून के मुसलमानों की रजतुमार्ग की। मस्जिद के अध्यक्ष नसीम अहमद ने बताया कि बादशाह ओरोजख के सदस्य रहे। मौलाना महफुज खाने नुबुख के संस्थापक हैं और यह अहम जिम्मेदारी को हमेशा ईमानदारी, सरकारी और इमानी हिस्सा के साथ निभाया उन्होंने हमेशा आओका के बचपन इत्य, दलौल और अमन के रास्ते को तबजीह ही। फ़ैदुस आँफ़ एक्कसर नामी तबीमा का क्याम किया।

महिलाओं के हाथ में 281 सहकारी समितियों की कमान

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स देहरादून। प्रदेश की सहकारी समितियों के चुनावों में महिला सराफिकरण की जबरदस्त छाप देखने को मिली है। प्रदेशभर की कुल 668 समितियों में से 281 समितियों की कमान महिलाओं के हाथों में रहेगी, जबकि 159 समितियों में उपाध्यक्ष पद पर भी महिलाओं ने जीत दर्ज की है। इसके अतिरिक्त विभिन्न समितियों के संचालक मण्डल में 2517 महिलाएँ का दबदबा, 159 बनी उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड के सहकारी चयनियों में टिखी महिला सराफिकरण की छाप

संचालक मण्डल में 2517 महिलाओं का दबदबा, 159 बनी उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड के सहकारी चयनियों में टिखी महिला सराफिकरण की छाप

ऐतिहासिक निर्णय लिया था। सरकार के इस निर्णय ने सहकारी समितियों में महिलाओं के प्रति निष्पक्ष को प्रभावित कर दिया। प्रदेश की कुल 671 प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एएम-पेयर्स) में हृदय चुनावों में कुल 6486 सहकारी निर्वाचित हुई जिनमें से लगभग 39 फीसदी यानी 2517 महिलाएँ निर्वाचित थीं। जिनमें अल्पसंख्यक जलपूर में 254, बागेश्वर 66, पंचपचास 1001, नैनीताल 213, तिथीराहट 281, ऊधमसिंह नगर 154, चाली 174, देहरादून 173,

प्रदेश की सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी सहकारिता आंदोलन में एक नई ऊर्जा और गति का संचार करेगी। साथ ही महिलाओं के नेतृत्व से सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता जैसे मूल्य और अधिक मजबूत होंगे।

डॉ. धन सिंह रावत, सहकारिता मंत्री, उत्तराखण्ड। हरिद्वार 191, पौड़ी 382, रुद्रप्रयाग 138, टिहरी 237 तथा उत्तरकाशी में 153 महिलाएँ संघ, जलक मंडल में निर्वाचित हुईं। सितें संचालक मण्डल में ही नहीं बल्कि महिलाओं ने पदाधिकारी स्तर के पदों पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। प्रदेश की कुल 668 निर्वाचित समितियों में से 281 समितियों की कमान महिलाओं के हाथों में रहेगी। जिनमें अल्पसंख्यक जलपूर में 25, बागेश्वर 7, चम्पावत 10, नैनीताल 19,

पिथौरागढ़ 35, ऊधमसिंह नगर 18, चमोली 16, देहरादून 15, हरिद्वार 21, पौड़ी 58, रुद्रप्रयाग 14, टिहरी 30 तथा उत्तरकाशी की 13 समितियाँ शामिल हैं। इसी प्रकार 159 समितियों में महिलाओं ने उपाध्यक्ष के पद पर जीत हासिल की। सहकारी समितियों की महिला प्रतिनिधित्व ने देश के सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने का एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला नेतृत्व और सामुदायिक विकास को भी सशक्त बनायेगा।

उपनल कर्मचारियों की मांगे माने सरकार: आर्य

देहरादून शाह टाइम्स)। नेता प्रतिपक्ष शरणागत और ने कहा कि, सरकार को कुटुंब विहंगम लेने में 2018 के उच्च न्यायालय के आदेश का समान करने हुए उपनल कर्मचारियों को समान कानून के लिए समान वेतन और नियमितीकरण की मांग मान लेनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, 2018 के उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करनी की मांग को लेकर उपनल कर्मियों विपक्षी दिनों से धरने पर डटे हुए हैं इस धरने के दौरान 2 उपनल कर्मियों को मृत्यु भी चुकरी है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, कुटुंब विहंगम में न्यायालय के आदेश का पालन करने के बजाय सरकार ने पहले उच्च न्यायालय को इस्तेमाल में अपील की फिर उच्चतम न्यायालय में भी याचिका और नुविचकार याचिका दायित्व की है। लेकिन सरकार को कभी भी सफलता नहीं मिली, उच्च न्यायालय को न्यायालय से झड़ भी झड़ी है।

देश में गो हत्या रोकने में सरकार रही असफल : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

शाह टाइम्स संवाददाता

उत्तरकाशी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि गो हत्या माता है सनातन धर्म में ब्राह्मण, देव, सेत और गो ही इस धर्म के चार खंभे हैं। इन्हीं पर भारतीय संस्कृति संरक्षित है। हमें गो की बचाने के लिए संकल्प लेना होगा। चौपड़ाधर में 1 वर्ष 11 दिन तक चलने वाली गो माता की आराधना के रूप में गोपाल मणि महाराज जी व सीता शरण महाराज जी द्वारा गी प्रतिष्ठा संकृत सिद्ध अनुष्ठान एवं दिव्या धनु मानस गो कथा में पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती रविवार को पहुंचे। उन्होंने कहा कि चौपड़ा धाम नाराज की भूमि है यह स्थान सिद्ध पीठ है। उन्होंने हिंदुओं से आग्रह करते हुए कहा कि वे गो को धक्का मार रहे हैं दूध तक तो

उत्तरकाशी:

चौपड़ाधर में 11 दिनों से चल रही गो कथा में पहुंचे शंकराचार्य



गोप जीक है और उसका बच गो को सड़कों में डाल रहे हैं। इस बात के प्रमाण दू को गाय से बहुत कुछ नहीं हमसे श्रेष्ठ धन भी माता है। उन्होंने कहा कि आज हर घर में गोपाल का सम्पन्न है। आर्थिक, रोग, और कष्ट सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक विपत्ति समाधान की सेवा है गो सेवा से धन की प्राप्ति होती है जिससे आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। आर्थिक मजबूत होने ही रोग दूर भागते हैं और कष्टार घर के अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि गाय में आज एडिड हो गई है। उन्होंने विना व्यक्त करते हुए कहा कि देश में आज भी गो हत्या हो रही है, जिसे रोकने में सरकार

असफल रही है। इस दौरान कथा चला गोपाल मणि महाराज ने कहा कि 33 करोड़ देवी-देवताओं का चला-फिरता मंदिर इस पृथ्वी पर फैलल गी माता है। उन्होंने कहा कि बाजार के लिए अस्पताल, भक्त के लिए भावना तथा शिष्य के लिए गुरु है गी माता। गो की महानता को हट तो स्वयं राम-कृष्ण भी तय नहीं कर सकते। जिस गो माता का मन भी गोपाल के रूप में प्रथम पड़ा जाता है, वो गो माता किन्तु तय होगी। गो की जैसी तो कसब गी ही होती है। इस देश की सबसे पुरानी कथा गी सेवा ही है। वो भक्त गो माता की सेवा करते हैं, वे संस्कारी बनते हैं।

भाजपा ने तेज की पार्षद, सभासद और समितियां में नामित सदस्यों के लिए कयावद

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स देहरादून। नगर विकास में पार्षद एवं सभासद के साथ विभिन्न विभागों की समितियों में नामित सदस्यों के मनोनयन के लिए भाजपा संगठन ने अपनी कयावद तेज कर दी है। पार्टी का प्रयास है कि सरकार के कार्यों का अधिक से अधिक जवाब जताता एक पहुंचने के मकसद से होने वाली इन नामित नियुक्तियों में अतिरिक्त अनुसर योग्य व्यक्तियों का चयन हो। प्रदेश महासभा की कुटुंब परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखण्ड नगर विकास युवायु पृष्ण होने के बाद सरकार को नगर निगम में पार्षद और नगरपालिका एवं नगर पंचायतों में सभासद, तय नियमावली के अनुसार नामित करने जा रही है। इसी तरह विभिन्न सरकार, ती विभागों की समितियों में भी उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की भी शीघ्र



मनोनयन किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें प्रमुख रूप हैं, समाज कल्याण, विद्यालय एवं शिक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, सांस्कृतिक स्वास्थ्य एवं विकास शिक्षा, उद्योग, पंचजन, कोशल विकास एवं संसाधन आदी विभागों में सदस्यी एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम विकास समिति में एक उपाध्यक्ष और सदस्य नामित होने हैं, जो जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर भी नामित

किए जाते हैं। उन्होंने कहा, राज्य के विकास और जनता को अधिक लाभ दिलाने की दिशा में नामित होने वाले व्यक्तियों में योगदान, अतिरिक्त, उपलब्धता, सक्रियता, क्षेत्रीय, सामाजिक समीकरण का संज्ञान रखा जाता है। हमें पार्टी संगठन का प्रयास है। अच्छे लोगों का चयन हो ताकि सरकार के काम सुचारु रहे और जनता की समस्या को आसानी से निराकरण हो सके। विहाजा इन सभी मानकों पर जो भी कार्यकर्ता उचित पाए जाते हैं उनका अधिक से अधिक मनोनयन करने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। फिलहाल इस विषय को लेकर हमारी कयावद तेज हो चुकी है और सक्षम एवं योग्य कार्यकर्ताओं की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सदरों में सिर से छिन गया छत का सहारा विकासनगर। सहकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगाता जारी है, जिससे अतिक्रमणकारी एक बार हड़कप मच गया है। रविवार को तहसील विकासनगर को टीम ने दककणी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू की है। प्रशासन की टीम ने पूर्व में भी डाकपल्ल, नवागढ़, धीमावाला, हकनारी, डालीपुर और कुल्लहा क्षेत्र में युवजीवीनगर की सहकारी जमीनों पर बड़े पैमाने पर हुए अवैध अतिक्रमण को कब्जा करवा था। इस बार भी इन्हीं इलाकों में बीते सप्ताह विचित्र किए गए 116 अवैध कब्जों और उस पर किए गए निर्माणों को बुलडोजर की मदद से कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं महिलाएँ कार्रवाई को अंगरे लेते हैं, उल्टा करवाता के अंगरे लेते हैं, उल्टा करवाता की कामे ऊपर से बुलडोजर चला कर मकान ध्वशीकरण की कार्यवाही करेगा।

कृषि मंत्री ने प्रशिक्षण दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

■ पलायन को रोकने में कृषि और बागवानी का बहुत बड़ा योगदान : जोशी

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स देहरादून। प्रदेश के कृषि मंत्री गोपेश जोशी ने आज हार्थीबहुदला स्थित एक कालिय से नवाबों योजनागत थ्यापि पलीहाडस के 05 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु जनपद देहरादून के चयनी 28 कृषकों के दल को गोविंद बलराम पंतनम विषयविशालय के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के आग रोगों को रोकने में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि नवाबों के मध्य में 50 बजट पलीहाडस से प्रशिक्षण कर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में



बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। कृषि मंत्री गोपेश जोशी ने आज यह 28 कृषकों को रोकने में कृषि और बागवानी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में लौटे प्रवासी सबसे अधिक कृषि और बागवानी क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। ऐसे में सरकार उन्हें कृषि और बागवानी आधारित आजीविका से

जोड़कर आयुनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के लिए रवाना हो रहा यह 28 कृषकों को रोकने में कृषि और बागवानी के कार्य में मदद दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पलीहाडस के संचालन व प्रशासन के लिए विभागों द्वारा नियुक्त तकनीकी सहानता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उत्पादन में और बढ़ोतरी सुनिश्चित हो सके।

उत्प्रेक्षणीय वृद्धि संभव है। उन्होंने कहा कि निर्वाचित वतांतरण से किसानों को बेहतर उत्पादन क्षमता और उच्च गुणवत्ता के कारण बाजार में दो से तीन गुना तक मूल्य प्राप्त होता है। उन्होंने यह भी कहा कि पलीहाडस के संचालन व प्रशासन के लिए विभागों द्वारा नियुक्त तकनीकी सहानता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उत्पादन में और बढ़ोतरी सुनिश्चित हो सके।

किरकार का इशारेगा।” हमसूर किरकार की मरते नहीं हैं। ये हमसूर जितना करीब मरते हैं, “बसले की भावना से भरे निरालाकिर किरकार एखन हुआ किरकार का दूसर फिलिक के सभी कलकारों के वेदनीयधिविष के साथ मुलक के अपेरी पधियम निरालाईडन बनसु मसूरकें प्योशिरातन अपेरीडियम में मसूर किरकार का दूसर का भयमम तरीकें से धिरुपट में दिखलाया गुन। उन जनकारों ने हरे किरकार निमिता रागामा में हरे ने बताता है कि हमसूर किरकार फिल्टर दूसर रिलीज के इतने गुन अवसर पर बहुत ही फिल्टर खुलना मौलक हुआ। हे फिल्टर को आने सोलें।

12 प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान
प्राप्त कर डायनेस्टी ने लहराया परचम

बिड़-पत्र

[illegible][illegible]

शाह टाइम्स

सम्पादकीय

सोमवार , 24 नवम्बर 2025

चंडीगढ़ पर फिर सियासत

पंजाब और हरियाणा के बीच स्थित केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को लेकर फिर सियासत शुरू हो गई है। यह वही चंडीगढ़ है, जिसको लेकर पंजाब और हरियाण समय-समय पर एक-दूसरे के सामने आते रहे हैं। चंडीगढ़ का विवाद नया नहीं है, लेकिन यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। दोनों प्रदेशों के सचिवालय यहीं स्थित है। 2002 में जब ओमप्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तब पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से चंडीगढ़ को मांगा था और इसके बदले हरियाणा ने पंजाब के हिन्दी भाषी क्षेत्र अबोहर और फाजिल्का मांग लिए थे। इसके बाद से ये विवाद चला आ रहा है। अब केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। लोकसभा और राज्यसभा के बुलेटिन में बताया गया है कि सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र (1 दिसंबर से शुरू) में संविधान (131)वां संशोधन) विधेयक 2025 पेश कर सकती है। अगर ये बिल अपने मौजूदा रूप में पास होता है, तो संभावना है कि चंडीगढ़ के लिए एक स्वतंत्र प्रशासक नियुक्त किया जा सकेगा। जैसा कि पहले यहाँ स्वतंत्र मुख्य सचिव हुआ करते थे। प्रस्तावित बिल पर बवाल इसलिए है, क्योंकि ये बदलाव चंडीगढ़ की प्रशासनिक पहचान को पूरी तरह बदल देगा। अभी तक चंडीगढ़ एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके संचालन में पंजाब की भूमिका मानी जाती है और पंजाब के राज्यपाल उसकी कमान संभालते हैं। एसएसपी और डीसी जैसी प्रमुख नियुक्तियां भी पंजाब और हरियाणा कैंडर से होती हैं, इसलिए यह शहर दोनों राज्यों की साझा राजधानी की तरह काम करता है, लेकिन प्रस्तावित संशोधन के बाद चंडीगढ़ का मॉडल बदल जाएगा। इसे राष्ट्रपति के सीधे नियंत्रण वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, जिसमें एक अलग प्रशासक या उपराज्यपाल नियुक्त होगा। हालाँकि गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया कि चंडीगढ़ की शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का बदलाव करने या पंजाब और हरियाणा के साथ उसके पारंपरिक संबंधों को प्रभावित करने की कोई बात नहीं है। इस मुद्दे पर पंजाब की राजनीति गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने इसे पंजाब के अधिकारों पर हमला बताते हुए केंद्र सरकार पर तीखे आरोप लगाए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रस्तावित संशोधन बिल चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकारों को कमजोर करेगा। सीएम मान ने इसे पंजाब के हितों के विरुद्ध बताते हुए कहा था कि चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब का है और राज्य अपने अधिकार से पीछे नहीं हटेगा। मान के पोस्ट के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र पर सीधा हमला बोला था और कहा था कि संविधान संशोधन के नाम पर चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। केजरीवाल ने इसे पंजाब की आत्मा को चोट पहुंचाने वाला कदम बताया था। फिलहाल यह साफ हो गया है कि केंद्र सरकार के स्तर पर अभी कोई बदलाव न तो अंतिम रूप ले चुका है और न ही संसद में इसे तुरंत लाने की योजना है। ऐसे में चंडीगढ़ को लेकर चल रही बयानबाजी पर विराम लगने की संभावना है, हालाँकि राजनीतिक हलकों में बहस आगे जारी रहने की पूरी उम्मीद है।

नोटबंदी और लॉकडाउन की याद ताजा

काम के दबाव में बीएलओ की मौत के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, वास्तविक संख्या उनसे बहुत अधिक है, यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है और इस पर सबको ध्यान देना जरूरी है, एसआईआर इसके लिए जिम्मेदार है, भाजपा की वोट चोरी बीएलओ के लिए जानलेवा रूप ले चुकी है,काम के भार से बीएलओ और पोलिंग अधिकारी लगातार आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, मेरी हर एक परिवार, जिसने अधिकार को खोया है, उनके प्रति गहन संवेदनाएं हैं, इन पंडित परिवारों को न्याय कौन दिलाएग, भाजपा चोरी की सत्ता की मलाई खाने में व्यस्त है और आयोग मुक्त दर्शक बने तमाशा देख रहा है, हड़बड़ी में बिना योजना के जबरन एसआईआर लागू करना नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की याद दिलाता है।

-मल्लिकार्जुन खड्गे
कांग्रेस अध्यक्ष

पिछले दिनों एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। इस पोस्ट में सेवानिवृत्त कर्नल एएन रॉय का बयान सेना के उस वर्ग की भावना को स्पष्ट करता है, जो लगातार आतंकवाद, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता वाले इलाकों में डटा रहता है। जब सैनिक सीमाओं या कश्मीर जैसे ‘संवेदनशील क्षेत्रों’ में आतंकवाद का सामना करते हैं, तब उन्हें कुछ फैसले अक्सर सेकंडों में लेने पड़ते हैं। इसमें औपचारिकताओं के लिए समय नहीं होता। जो भी निर्णय लेना होता है वह उन सैनिकों को दिए गए प्रशिक्षण और अपने विवेक से ही लेना पड़ता है।

इस पोस्ट ने सीधे सवाल उठाया, क्या आपने कभी अपने बेटे को खोया है? यह व्यवस्था से उपजी पीड़ा और असंतोष की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इसका मूल भाव यही है कि जब सैनिक आतंकवादी का सामना करता है, तो वह कानून या न्यायालय की व्याख्याओं से अधिक, अपने प्रशिक्षण और परिस्थिति पर ही निर्भर करता है। बाद में उस पर अभियोग या अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगना उसे अपमानजनक महसूस होता है। दूसरी ओर, सर्वोच्च न्यायालय की दृष्टि संविधान की मूल भावना, ‘हर नागरिक के मौलिक अधिकार’ से निर्देशित होती है। न्यायालय किसी सेना या व्यक्ति का विरोध नहीं करता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि ‘राज्य की शक्ति’ जवाबदेही से परे न हो। कश्मीर या किसी अशांत क्षेत्र में नागरिकों पर अत्याचार या फर्जी मुठभेड़ों के आरोप अक्सर सामने आते हैं। यदि जांच का हक छीन लिया जाए, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठेंगे। न्यायालय यह नहीं कहता कि आतंकवादी को बचाया जाए, बल्कि यह मांगता है कि निर्दोष लोग आतंकवादी समझकर मारे न जाएं। यही ‘न्याय का नैतिक आधार’ है।

पोस्ट में आतंकवादियों के मानवाधिकारों को लेकर जो कटाक्ष किया गया है, वह भावनात्मक प्रतिक्रिया है, लेकिन मानवाधिकारों का सार आतंकवादी के प्रति करुणा नहीं, बल्कि बिना भेदभाव सिद्धांतों पर आधारित न्याय को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में है। जब किसी संरिध की मौत की जांच होती है, तो लक्ष्य अपरा. धियों को बचाना नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग को रोकना होता है। वैश्विक संदर्भ में भी ची. रि.का, ब्रिटेन या फंस जैसे देशों में वॉर क्राइम्स या एक्ससिव फोर्स पर सवाल उठते रहें हैं। सशक्त लोकतंत्र वे हैं जो अपने संस्थानों से प्रश्न पूछने का साहस रखते हैं। यह साफ है कि सेना को अपराधी न मानें और न्यायपालिका को देशविरोधी न कहें।

संविधान के अंतर्गत नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना, अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के नियंत्रण को सुनिश्चित करना, और नागरिकों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षित रखना, एक जटिल संतुलन है।

जबकि बीएसपी ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है, उसने आकाश आनंद द्वारा बनाई गई एक अच्छी तरह से सोची-समझी रणनीति के बाद केवल 40 सीटों पर चुनाव लड़ा और एकमात्र सीट जीती। यह चुनाव एक मजबूत नेता के रूप में उभरे आकाश आनंद के लिए अग्निपरीक्षा था। चुनाव की खूबसूरती यह थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक रैली को संबोधित किया और आकाश आनंद ने रैलियों को संबोधित किया और पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया और चुनाव लड़ रहे पदयात्रा का आयोजन किया।

सेना बनाम सर्वोच्च न्यायालय बनाम मानवाधिकार



दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक निष्ठा के दो मजबूत स्तंभ हैं। समस्या तब आती है जब संवैधानिक प्रक्रिया को देश विरोधी साजिश या सैनिक कार्रवाई को न्याय की हत्या मान लिया जाता है। इससे संवाद में विघटन और अविश्वास बढ़ता है। समुचित समाधान यही है कि सेना को ‘ऑपरेशनल प्रोटेक्शन’ मिले, ताकि तत्काल कार्रवाई में की गई गलती अपराध न माना जाए, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग करने पर न्यायिक जांच की प्रक्रिया बनी रहे। ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया पर राष्ट्रभक्ति को भावना को सीधा स्पर्श करते हैं। खतरा इस बात में है कि भावनाओं की लहरों में तथ्य और कानूनी सीमाओं की अनदेखी होने लगती है। न्यायपालिका, सेना और मानवा. धिकार, ये विरोधी नहीं बल्कि लोकतंत्र के पूरक अंग हैं। सोशल मीडिया पर एकांगी नैरेटिव अंततः सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करता है। भारत में सेना, सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार को लेकर टकराव की घटनाएं केवल हाल ही की नहीं, बल्कि देश के इतिहास में समय-समय पर सामने आई हैं।

18वीं शताब्दी में, कोलोनियल शासन के दौरान सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन कार्डसिल के बीच अधिकार को लेकर पहली

बड़ी भिड़ंत कोसिजुरा मामला में देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सेना का इस्तेमाल करते हुए अपनी शक्तियां बढ़ाने का प्रयास किया, जबकि गवर्नर जनरल इन कार्डसिल ने अदालत के आदेशों को चुनौती दी और सेना को अदालत के खिलाफ तैनात कर दिया। यह विवाद बंगाल ज्यूडिकेचर एक्ट 1781 के पास होने तक चलता रहा, जिसने अदालत को सीमाएं तय कर दीं और टकराव का अंत किया। इस मामले ने जता दिया कि अधिकारों की अस्पष्टता शक्ति संघर्ष का हमेशा केंद्र रही है।

1945 में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर देशद्रोह और हत्या के आरोप लगे और उन पर कोर्ट मार्शल चलाया गया। ब्रिटिश सरकार ने इन सैनिकों की गतिविधियों को किंग के खिलाफ युद्ध माना, जबकि भारतीय जनता और नेताओं ने देशभक्ति की भावना को कानूनी प्रक्रिया के विरोध में जोरदार तरीके से रखा। इस संघर्ष में अदालत के आदेशों और जनता के मानस के बीच गहरा विभाजन आया। नगा पीपल्स मूवमेंट बनाम भारत सरकार केस में सर्वोच्च न्यायालय में AFSPA की वैधता को चुनौती दी गई, लेकिन अदालत ने यह माना कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सेना को अतिरिक्त अधिकार देने का प्रावधान संविधान के खिलाफ नहीं। फिर भी, अदालत ने

बसपा का महागठबंधन को जोर का झटका धीरे से



लसूद हसन

एक सोची-समझी रणनीति के तहत बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में सरकार बनाने के न सिर्फ महागठबंधन के सपने को चकनाचूर कर दिया, सियासी गलियारों में चर्चा है कि बसपा ने बिहार में महागठबंधन को जोर का झटका धीरे से

ही नहीं दिया बल्कि राज्य में एक सीट जीतकर अपनी पेट भी बना ली। बसपा की इस जीत में असदुद्दीन औवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का भी सहयोग या रणनीतिक चाल मानी जा रही है। बीएसपी ने 243 में से 143 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा और 57 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवारों की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया, जिससे गठबंधन जादुई आंकड़े को छूने से काफ़ी पीछे रह गया।

बीएसपी ने राज्य में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में अकेली सीट जीतकर बिहार में बहुत बना ली है। बसपा प्रमुख मायावती ने दावा किया है कि अगर चुनाव श्वस्तंत्र और निष्पक्ष होते तो उनकी पार्टी को

कई और सीटें हासिल होतीं। बीएसपी उम्मीदवार सतीश कुमार यादव ने बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुमार को 30 वोटों के मामूली अंतर से हराकर रामगढ़ सीट जीती। बीएसपी ने रामगढ़ सीट पर कब्जा कर लिया है, जिसे पारंपरिक रूप से आरजेडी का गढ़ माना जाता है। राजनी. तिक विश्लेषकों ने दावा किया है कि यह परिणाम राज्य में एकमात्र सीट हासिल करके बीएसपी के प्रवेश का प्रतीक है। बीएसपी उम्मीदवार सतीश यादव ने बिहार में अच्छे प्रतिशत वोट हासिल करके बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुमार को हरा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आकाश आनंद को पार्टी में प्रोजेक्ट करने के इरादे से एक सीट जीतने के बाद उत्साहित और उत्साहित महसूस कर रहे हैं।

कार्यकर्ताओं का मानना ​​है कि आकाश आनंद ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती के असली उत्तराधिकारी हैं क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो ने आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी दी है, बीएसपी नेतृत्व ने कई बार उन्हें अपना उत्तराधिकारी नामित करने का संकेत दिया है। बामसेफ को पार्टी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने संकेत दिया है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, बीएसपी सुप्रीमो ने पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके नेतृत्व में काम करने का निर्देश दिया है, बिहार में विधानसभा चुनाव आकाश आनंद के निर्देशन में लड़ा गया था, बिहार में अन्य राजनीतिक दलों को बड़ा झटका

लगा है जबकि बीएसपी किसी तरह एक सीट हासिल करने में सफल रही है।

जबकि बीएसपी ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है, उसने आकाश आनंद द्वारा बनाई गई एक अच्छी तरह से सोची-समझी रणनीति के बाद केवल 40 सीटों पर चुनाव लड़ा और एकमात्र सीट जीती। यह चुनाव एक मजबूत नेता के रूप में उभरे आकाश आनंद के लिए अग्निपरीक्षा था। चुनाव की खूबसूरती यह थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक रैली को संबोधित किया और आकाश आनंद ने रैलियों को संबोधित किया और पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया और चुनाव लड़ रहे पदयात्रा का आयोजन किया। बीएसपी की रणनीति ने 57 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को बड़ा झटका दिया है और वे अधर में लटक गए हैं, रामगढ़ सीट पर बीएसपी की सफलता आकाश आनंद को पार्टी में स्थापित करने में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश में भी बी एस पी का गढ़ था। पार्टी ने यूपी में अपनी सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ क्रमशः एक और तीन बार गठबंधन किया है। बीएसपी ने 2007 में राज्य में आश्चर्यजनक वापसी की थी जब मायावती ने बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन 2022 में, बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में केवल एक सीट जीती और 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन किया।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

सेहत ही नहीं, त्वचा के लिए भी फायदेमंद हैं ये फल और सब्जियां

फलों और सब्जियों का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी जरूरी होता है। फलों और सब्जियों में मौजूद फाइबर न सिर्फ पाचन को स्वस्थ रखता है, बल्कि इससे आपको इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। इसके अलावा यह हमारी त्वचा के लिए भी लाभकारी होती है। कई ऐसे फल और सब्जियां होती हैं, जो स्किन को हेल्दी बनाए रखने में सहायक होती हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इन फलों और सब्जियों के बारे में बताते जा रहे हैं। जिनके सेवन से आपको सेहत संबंधी लाभ मिलने के साथ ही स्किन संबंधी फायदे भी मिलते हैं।

शकरकंद

आपको बता दें कि सेहत के साथ-साथ शकरकंद स्किन के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। शकरकंद में बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो हमारी त्वचा को नेचुरल रूप से हेल्दी रखने में मददगार होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी पाई जाती है। जो त्वचा संबंधी इंफेक्शन के खतरे को कम करता है। शकरकंद को उबाल कर खाने से त्वचा को फायदा मिलता है।

एवोकाडो

स्किन के लिए एवोकाडो का सेवन भी लाभकारी माना जाता है। एवोकाडो में विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके सेवन से आपकी त्वचा अंदर से साफ होता है। जब स्किन अंदर से साफ होती है तो बाहर भी इसका निखार साफ पता चलता है। आप चाट या फिर शेक के तौर पर भी एवोकाडो का सेवन कर सकते हैं।

खीरा

खीरा में पानी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इसके सेवन से त्वचा हाइड्रेड रहती है। वहीं खीरे में एंटी-ऑक्सीडेंट्स भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मददगार होता है। खीरे के नियमित सेवन से स्किन हाइड्रेंट रहने के साथ ही मॉइस्चराइज रहती है।

संतरा

विटामिन सी से भरपूर संतरा त्वचा की सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। संतरा में आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो स्किन को नेचुरल तरीके से हेल्दी और ग्लोइंग रखता है। साथ ही संतरे के सेवन झुर्रियां कम होने के साथ कोलेजन बढ़ता है।

पपीता

हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में पपीता भी अहम भूमिका निभाता है। पपीता में मिनरल्स के साथ-साथ विटामिन-ए, विटामिन बी और विटामिन सी पाया जाता है। जो स्किन को हेल्दी बनाने में मदद करता है। साथ ही यह त्वचा को हाइड्रेट भी रखता है। ऐसे में आप रोजाना पपीता का सेवन कर सकते हैं।

अनानास

स्किन को हेल्दी रखने में अनानास भी मददगार होता है। अनानास में विटामिन ए, सी की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसमें मौजूद विटामिन ए और सी त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है। वहीं इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। जो त्वचा को जल्दी रिकवर करते हैं। इसके सेवन से आपकी त्वचा हील होने के साथही ग्लोइंग भी बनती है।

दही का रायता ही नहीं बल्कि कई तरीके से बनाएं चटनी

भारतीय खाने में दही को जरूर शामिल किया जाता है। अक्सर लोग सादा सदी या फिर रायता खाना पसंद करते हैं। बता दें कि पेट के लिए दही काफी फायदेमंद होता है। वहीं इसके सेवन से गट हेल्थ भी बेहतर होती है। भारतीय खाने में चटनी काफी फेमस है। सब्जी और फल से लेकर नारियल तक की चटनी बनाई जाती है। वहीं बोरिंग खाने के स्वाद को चटनी स्वादिष्ट बना देती है। इसलिए अधिकतर घरों में चटनी बनाकर खाई जाती है। लेकिन क्या आपने दही चटनी खाई है। अगर आपका जवाब नहीं है, तो आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको दही की चटनी बनाने की विधि के बारे में बताते जा रहे हैं। आप कई चीजों और कई तरीकों से दही चटनी बना सकते हैं। आइए जानते हैं दही की चटनी बनाने की रेंसिपी के बारे में।।।

राजस्थानी स्टायल में दही चटनी

पूरे भारत देश में राजस्थानी स्टायल की चटनी फेमस है। राजस्थान में बनने वाली लहसुन चटनी वाकई स्वाद में बेहद लाजवाब होती है। अगर आपने राजस्थानी दही-लहसुन की चटनी नहीं खाई है, तो आप इस रेंसिपी को घर पर ट्राई कर सकते हैं।

ऐसे बनाकर करें तैयार

- राजस्थानी स्टायल की दही चटनी बनाने के लिए सूखे लाल मिर्च को पानी में भिगो दें।
- फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें लहसुन की कलियों को भुगू होने तक भूयें।

- फिर लहसुन में 2 चम्मच धनिया के बीज, 1 चम्मच जीरा, सूखा लाल मिर्च और आधा चम्मच काली मिर्च डालकर धीमी आंच पर पका लें।
- कुछ देर में चटनी से खुशबू आने लगेगी, तब गैस को बंद कर लें। वहीं पेट्ट को ठंडा होने के लिए छोड़ दें।
- जब पेट्ट ठंडा हो जाए तो इन्हें अच्छे से पीस लें।
- अब पीसे गए पेट्ट को तेल में डालकर तब तक पकाए जब तक उसका तेल अलग न हो जाए।
- फिर इसमें 1 चम्मच जीरा, चुटकी भर हॉग ,करी पत्ता, 1 चम्मच सरसों और फेटा हुआ दही अच्छे से मिक्स कर दें।
- करीब 5 मिनट तक चलाने के बाद गैस बंद कर दें।
- इस तरह से आपको दही-लहसुन की राजस्थानी स्टायल चटनी बनकर तैयार है।
- इसे आप सादे चावल से लेकर स्नैक्स तक के साथ खा सकते हैं।
- ऐसे बनाएं परफेक्ट चटनी**
- चटनी को घर टेस्टी बनाने के लिए ताजे लहसुन का इस्तेमाल करें।
- क्योंकि लहसुन के खराब होने पर चटनी का स्वाद बिगड़ जाएगा। इस चटनी के लिए अंकुरित लहसुन का इस्तेमाल न करें।
- वहीं ताजे दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर दही

- खट्टा होगा तो चटनी उतनी स्वादिष्ट नहीं होगी।
- अधिक मात्रा में इसमें तेल का उपयोग न करें।
- वही चटनी बनने के बाद इसको सही से स्टोर करें। जिससे कि यह 2-3 दिन चल जाए।
- आप कांच के जार में चटनी को स्टोर करके रख सकती हैं।
- चटनी अधिक पतली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि चटनी गाढ़ी अच्छी लगती है।
- दही हरी मिर्च चटनी की रेंसिपी**
- हरा मिर्च भी खाने के स्वाद को दोगुना करता है। हरी मिर्च का इस्तेमाल खाने को चटपटा करने के लिए किया जाता है। आप चाहें तो हरी मिर्च की चटनी भी बना सकती हैं। आज हम आपको दही और हरी मिर्च की चटनी की रेंसिपी के बारे में बताते जा रहे हैं। आप भी इसे घर पर बनाकर खा सकते हैं। हरी मिर्च की चटनी बनाने के लिए हरी मिर्च को अच्छे से धो लें। फिर इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अगर आप स्वादिष्ट चटनी बनाना चाहते हैं, तो मिर्च को मिक्सी की जगह सिलबट्टे पर पीसें। इससे चटनी का स्वाद दोगुना हो जाएगा। हरी मिर्च को बारीक पीसने के बाद इसमें दही मिक्स कर लें। फिर इसमें हिंग, जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक मिला लें। इस तरह से आपको दही-हरी मिर्च की चटनी बनकर तैयार हो जाएगी।

वेनेजुएला में तख्तापलट करा सकता है अमेरिका

सीक्रेट ऑपरेशन की तैयारी, इलाके में घेराबंदी कर रहा, टकराव की आशंका बढ़ी

वाशिंगटन। अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में वेनेजुएला के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू हो सकता है। ट्रम्प प्रशासन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का तख्तापलट भी करवा सकता है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी रायटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दी है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक शुरुआत सीक्रेट ऑपरेशन से हो सकती है। अभी साफ नहीं है कि यह कदम कब उठाया जाएगा और इसका दायरा कितना बड़ा होगा, लेकिन इतना जरूर है कि ट्रम्प प्रशासन इसे लेकर काफी गंभीर है। हाल के हफ्तों में अमेरिकी सेना ने कैरेबियाई इलाके में बड़ी संख्या में जहाज, विमान और सैनिक तैनात किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन और सीक्रेट एजेंसी सीआईए इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि राष्ट्रपति



■ ट्रम्प प्रशासन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर गिराएगा गाज

ट्रम्प ड्रग तस्करी रोकने के लिए हर तरह की ताकत का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। कैरेबियाई इलाके में बीते कुछ महीनों से अमेरिकी सेना का जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है। सबसे बड़ा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर 'जैराल्ड आर फोर्ड' और उसके साथ कई युद्धपोत, एक परमाणु पनडुब्बी और एफ-35 विमान तैनात किए गए हैं। अमेरिकी लंबे समय से मादुरो पर आरोप लगाता रहा है कि वह ड्रग तस्करी में शामिल हैं,

हालांकि मादुरो इन आरोपों को साफ तौर पर झूठा बताते हैं। दूसरी तरफ मादुरो का कहना है कि अमेरिका उन्हें सत्ता से निकालना चाहता है, लेकिन देश और सेना किसी भी बाहरी दखल का विरोध करेगी। अमेरिकी सेना सितम्बर से अब तक दर्जनों ड्रग बोट्स पर हमले कर चुकी है, जिनमें 80 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अमेरिका बिना सबूत के लोगों को मार रहा है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। दो महीने पहले वेनेजुएला की बोट पर अमेरिकी हमले का फुटेज। इस हमले में 3 लोग मारे गए थे। हालात और तनावपूर्ण तब हो गए जब अमेरिका की फंडरल एक्विशन एजेंसी (एफएए) ने वेनेजुएला के ऊपर उड़ान भरने को लेकर चेतावनी जारी कर दी। एफएए ने कहा कि वेनेजुएला के एयर स्पेस में मिलित एक्टिविटी बढ़ गई है और जीपीएस सिस्टम में दखल जैसी समस्याएं देखी गई हैं, जो उड़ानों के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।

मोदी ने जमैका के प्रधानमंत्री से की मुलाकात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जोहान्सबर्ग में जी-20 समिट के दौरान जमैका के अपने समकक्ष एंड्रयू होलनेस के साथ बातचीत की और कैरेबियाई देश के साथ भारत के मजबूत और बढ़ते रिश्तों को पक्का किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर किया कि जोहान्सबर्ग में जी-20 समिट के दौरान जमैका के प्रधानमंत्री मिस्टर एंड्रयू होलनेस से बातचीत की। भारत और जमैका इतिहास से बनी और सांस्कृतिक जुड़ाव से मजबूत हुई दोस्ती से बंधे हैं। हमारी पार्टनरशिप मिलकर तरक्की करने के गहरी प्रतिबद्धता के साथ बढ़ती जा रही है।



प्रयागराज। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए मतदाता फॉर्म जमा करते हुए।

वियतनाम में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 90 लोगों की मौत

हनोई। मध्य वियतनाम इलाके में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या रविवार को बढ़कर 90 हो गई। समाचार पत्र थान निएन ने वियतनाम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हवाले से ये जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 12 लोग अभी भी लापता हैं। तेज बारिश और बाढ़ से इलाके में 1154 घरों और 80800 हेक्टेयर से ज्यादा चावल और दूसरी फसलों को नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह ने मध्य प्रांतों में गंभीर बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के उपाय बढ़ाने को कहा है। वियतनाम न्यूज एजेंसी ने बताया कि वियतनामी सरकार ने इस आपदा से बुरी तरह प्रभावित इलाकों की सहायता के लिए 700 बिलियन वियतनामी डॉंग (लगभग 26.6 लाख डॉलर) की आपातकालीन मदद दी है।

गाजा में फिर एयरस्ट्राइक, 24 लोगों की मौत

सीजफायर के बाद भी नहीं मान रहा इजरायल, 54 लोग घायल, अस्पतालों ने की पुष्टि

गाजा/तेल अवीव। इजरायली डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) ने हमला ठिकानों में हवाई हमले किए, जिनमें 24 लोगों की मौत हो गई और 54 लोग घायल हुए। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली सेना ने दावा किया कि ये हमले उन हमला लड़कों के जवाब में किए गए, जिन्होंने संघर्षविराम के बावजूद इजरायल-नियंत्रित क्षेत्र में घुसकर सैनिकों पर गोली चलाई। सेना ने इस घटना को सीजफायर का गंभीर उल्लंघन बताया।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहु के कार्यालय ने कहा कि कार्रवाई में हमला के पांच बरिष्ठ सदस्य मारे गए, जबकि हमला से आरोप लगाया कि इजरायल बहाने बनाकर युद्ध फिर शुरू करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका द्वारा कराए गए युद्धविराम के बावजूद इजरायल अब तक गाजा में 394 हमले कर चुका है, जिनमें 300 से अधिक लोग मारे गए और करीब 700 से ज्यादा घायल हुए। इससे पहले बुधवार को भी आईडीएफ ने गाजा में हमले कर 25 लोगों को मार दिया था, जब इजरायल ने दावा किया कि हमला से युद्धविराम का उल्लंघन किया है। गाजा में कई इलाकों पर एक के बाद एक हुए हमलों ने पूरे माहौल को दहशत से भर दिया। गाजा सिटी के रिमाल क्षेत्र में एक वाहन को



■ गाजा सिटी के रिमाल क्षेत्र में एक वाहन को एक हमले में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए

निशाना बनाए गए हमले में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए। शिफा अस्पताल के डाक्टरों के मुताबिक, घायलों में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं। इसी के साथ, अल-अवदा अस्पताल के पास एक मकान पर हुए हमले में 3 लोगों की जान गई और 11 घायल हुए। नुसरत कैंप में एक घर पर किए गए हमले में सात लोगों की मौत हुई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। दैर अल-बलाह में एक और आवासिय घर को निशाना बनाए जाने से तीन लोगों की मौत हुई, जिनमें एक महिला भी थी। दैर अल-बलाह के खालिल अबू हातब ने भयावह दृश्य बताते हुए कहा अचानक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यह कैसा संघर्षविराम है? यहां तो कोई भी जगह

सुरक्षित नहीं है। गौरतलब है कि सात अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इजरायल-हमला संघर्ष में अब तक 69733 लोग मारे जा चुके हैं, 170000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा, 7 अक्टूबर 2023 के हमला हमले में इजरायल में 1,139 लोगों की मौत हुई थी और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया था। संघर्षविराम के दौरान भी मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, क्योंकि एक हमलों के अलावा मलबे से पुराने शव भी निकाले जा रहे हैं। मंत्रालय का कहना है कि मृतकों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने दावा किया है कि फलस्तीनी संगठन हमला पूरे यूरोप में आतंकी हमलों की साजिश रच रहा है। इसके लिए हमला द्वारा स्वीपर सेल द्वारा आतंकी नेटवर्क तैयार किया जा रहा है।

अब यूरोप में हमले की साजिश रच रहा हमला, इजरायली खुफिया एजेंसी ने किया दावा

एक बयान में मोसाद ने कहा कि यूरोपीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है और हथियारों को जम्मा किया है। साथ ही कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और हमलों को रोकना है। मोसाद का कहना है कि हमला आतंकी नेटवर्क यूरोप में यहूदी समुदाय और इजरायली नागरिकों पर हमलों की साजिश रच रहा था। जर्मनी, आस्ट्रिया जैसे देशों में भी मोसाद ने स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वित ऑपरेशन चलाकर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पिछले सितम्बर में वियना में आस्ट्रिया की डीएनएस सिस्कारिटी सर्विस ने हथियारों का एक जखीरा ढूँढा, जिनमें विस्फोटक और हैंडगन शामिल थे। सुरक्षा बलों ने मोहम्मद नईम नामक संदिग्ध के बारे में पता लगाया, जांच में पता चला कि मोहम्मद नईम हमला के शीर्ष व्यूरी अधिकारी बासेम नईम का बेटा है, जो गाजा में हमला के शीर्ष नेता खलील अल-हया का करीबी बताया जा रहा है। मोसाद ने आरोप लगाया कि हमला का नेतृत्व भी यूरोप में आतंकी नेटवर्क तैयार करने में मदद कर रहा है। तुर्की में भी हमला के संगठन बेस की जांच चल रही है।

भारत ने सीओपी-30 में ब्राजील के नेतृत्व को सराहा

बेलेम। भारत ने ब्राजील के बेलेम में हुई संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सीओपी-30 में जलवायु न्याय की मजबूत आवाज बनकर उभरते हुए ब्राजील के समावेशी नेतृत्व को सराहना की। साथ ही जलवायु न्याय, समानता और वैश्विक एकजुटता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

भारत ने सम्मेलन में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों का स्वागत किया और सीओपी अध्यक्षा का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनका नेतृत्व समावेश, संतुलन और ब्राजील की सामूहिक प्रयास की भावना पर आधारित रहा, जिसने पूरे सम्मेलन को सकारात्मक दिशा दी। इसके साथ ही भारत ने ग्लोबल गोल आन एडप्टेशन (जीजीए) में हुई प्रगति का स्वागत किया। साथ ही कहा कि यह फैसले विकासशील

■ सम्मेलन में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों का स्वागत किया और सीओपी अध्यक्षा का धन्यवाद किया
■ यह कदम वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु न्याय को लागू करने में मदद करेगा

देशों की जरूरतों को समझते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का असर सबसे ज्यादा उन पर है। इस दौरान भारत ने दोहराया कि विकसित देशों की लंबे समय से चली आ रही जिम्मेदारी है कि वे विकसित देशों को पर्याप्त जलवायु वित्त उपलब्ध कराएं। भारत ने उम्मीद जताई कि 33 साल पहले रियो में किए गए वादों को अब पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ेंगे। भारत ने सीओपी-30 के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में 'जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म' की

स्थापना को बताया। भारत ने कहा कि यह कदम वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु न्याय को लागू करने में मदद करेगा। इस दौरान भारत ने एकतरफा, जलवायु के नाम पर लगाए जाने वाले व्यापारिक प्रतिबंधों का मुद्दा भी उठाया। साथ ही कहा कि ऐसे कदम विकासशील देशों को नुकसान पहुंचाते हैं और समानता तथा साझा लेकिन विभिन्न ज़िम्मेदारी के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। इस दौरान भारत ने यह भी स्पष्ट कहा कि जलवायु परिवर्तन का बोझ उन देशों पर नहीं डाला जाना चाहिए जो इसके लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं। भारत ने विज्ञान-आधारित, न्यायपूर्ण और समानता पर आधारित जलवायु कार्रवाई के प्रति फिर से प्रतिबद्धता जताई। अंत में, भारत ने ब्राजील और सभी देशों को धन्यवाद दिया।

दुबई एयर शो में रूसी विमानों ने नमांश सयाल को दी श्रद्धांजलि

दुबई। दुबई एयरशो के आखिरी दिन रूसी विमानों टीम ने तेजस हौसे में मारे गए विंग कमांडर नमांश सयाल को खास श्रद्धांजलि दी। रूसी विमानों ने आकाश में मिसिंग मैम फार्मेशन बनाया। रूसी टीम ने बताया कि उन्होंने एयर शो में अपना प्रदर्शन जारी रखा है। फिलहाल इसलिए लिया, ताकि उन भाइयों की याद में उड़ान भरी जा सके जो आखिरी नमांश सयाल की मौत हो गई थी। वे विमान से इजेक्ट नहीं कर पाए थे। डेमो फ्लाइट के दौरान तेजस नीचे आकर जमीन से टकराकर क्रैश हो गया।

अब उत्तरी अफ्रीकी देश में विद्रोह की चिंगारी भड़की

ट्यूनीशिया में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग

ट्यूनिस्। उत्तरी अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में भी सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। शनिवार को हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रपति काइस सादें के खिलाफ राजधानी ट्यूनिश की सड़कों पर उतरे।

लोग राष्ट्रपति सईद की बढ़ती कथित तानाशाही और जेल में बंद राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने अन्याय के खिलाफ बैनर के तले विरोध प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के परिवारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने किया। प्रदर्शन में हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारी शामिल हुए, जिन्होंने सरकार विरोधी नारे लगाए। ये प्रदर्शन ऐसे समय हो रहे हैं, जब ट्यूनीशिया आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर परेशानियों से घिरा हुआ है। इससे पहले गुस्सारा को ट्यूनीशिया के पत्रकारों ने भी सरकार विरोधी प्रदर्शन किए। दरअसल पत्रकारों ने प्रेस की आजादी को दबाने और प्रमुख नागरिक समाज संगठनों के खिलाफ कार्रवाई विरोध प्रदर्शन किया।



■ प्रदर्शन में हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारी शामिल हुए, जिन्होंने सरकार विरोधी नारे लगाए

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राष्ट्रपति सईद न्यायपालिका में दखलअंदाजी कर रहे हैं। साथ ही उन पर अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करने आरोप है। जेल में बंद विपक्षी नेता अब्देलहामिद जलसी की पत्नी मोनिया ब्राहिम ने कहा कि वह मार्च में इसलिए शामिल हुई

क्योंकि उनका मानना है कि कई ट्यूनीशियाई लोगों के साथ बर्बरता नाइसाफी हो रही है। मैं एक नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों की रक्षा करने आई हूँ। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कैदी अच्छी तरह जानते हैं कि वे अपने उसला, सिविल और पॉलिटिकल एक्टिविज्म के अपने संवैधानिक हक की कोमल चुकाने के लिए जेल में हैं, और आज ट्यूनीशिया में बनी सरकार उन्हें बंधक बनाए हुए है। हिरासत में लिए गए लोगों में से कुछ भूख हड़ताल पर हैं, जिसमें संवैधानिक कानून के प्रोफेसर जाहिर बेन म्बारेक भी शामिल हैं, जो 20 दिनों से जयादा समय से हड़ताल पर हैं। ट्यूनीशिया में बढ़ते दमन पर कई मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि 2022 के आखिर से 50 से ज्यादा लोगों को, जिनमें राजनेता, वकील, पत्रकार और एक्टिविस्ट शामिल हैं, अपनी बात कहने की आजादी, शांति से इकट्ठा होने या राजनीतिक गतिविधि चलाने के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए गिरफ्तार किया गया।

बांग्लादेश में विशेषज्ञों ने दी भीषण भूकंप की चेतावनी

कहा: अगर सरकार ने तुरंत सख्त कदम नहीं उठाए, तो नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता है

ढाका। बांग्लादेश में शुक्रवार सुबह आए 5.7 तीव्रता के भूकंप ने कम से कम 10 लोगों की जान ले ली और राजधानी ढाका समेत कई जिलों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया। वहीं विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह झटका किसी बड़े विनाशकारी भूकंप की आहट हो सकता है और अगर सरकार ने तुरंत सख्त कदम नहीं उठाए, तो नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता है। शनिवार को भी देश तीन हल्के झटकों से कांपता रहा, जिससे लोगों में डर और बढ़ गया। स्थानीय समाचार पत्र में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार का भूकंप 'ढाका की नाजुकता' को साफ दिखाता है। ढाका जिला प्रशासन ने 14 इमारतों में नुकसान की पुष्टि की है। वहीं राजतों में 50 से अधिक इमारतों में नुकसान की बात



■ ढाका जिला प्रशासन ने 14 इमारतों में नुकसान की पुष्टि की
■ राजतों पर वर्षों से निर्माण निगरानी में लापरवाही और कम स्ट्राफ होने के आरोप लगते रहे हैं

कही है, और मान रही है कि जांच आगे बढ़ने पर यह संख्या और बढ़ेगी। राजतों के चेयरमैन एम. रियाजुल इस्लाम ने कहा कि हमारी जांच जारी है। कई और इमारतें जोखिम भरी मिलेंगी। राजतों पर वर्षों से निर्माण निगरानी में लापरवाही और कम स्ट्राफ होने के आरोप लगते रहे हैं। बांग्लादेश भूकंप सांसायटी के उपाध्यक्ष प्रो. मुनाज अहमद नूर ने कहा कि राजतों

शहमेशा किसी बड़े हादसे के बाद ही जागता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश नेशनल बिल्डिंग कोड का कड़ाई से पालन अनिवार्य है। नूर के अनुसार, समस्या अक्सर डिजाइन में नहीं बल्कि कच्चे लागू होने में होती है, जैसे लोहे की मजबूती को गलत जगह लगाना। वहीं बांग्लादेश इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रो. मेहंदी

अहमद अंसारी ने चेतावनी दी कि जिन इमारतों में दरारें या नुकसान दिख रहा है, उनका तुरंत मूल्यांकन होना चाहिए। जोखिम के आधार पर उन्हें श्रेणीबद्ध कर कार्रवाई होनी चाहिए। यह हाल के झटके किसी बड़े भूकंप के पूर्व संकेत यानी पूर्वाभास भी हो सकते हैं। उनका कहना है कि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए, तो किसी बड़ी घटना में भारी जनहानि हो सकती है। वरिष्ठ भूकंप वैज्ञानिक सईद हुमायूँ अख्तर ने कहा कि भारत-बर्मा सबडक्शन क्षेत्र में बहुत ऊर्जा जमा हो रही है, जो किसी भी समय बहुत बड़े भूकंप का रूप ले सकती है। ढाका दुनिया के 20 सबसे भूकंप-जोखिम वाले शहरों में शामिल है। घनी आबादी, पुरानी और जर्जर इमारतें, और अवैध निर्माण इस और ज्यादा असुरक्षित बनाते हैं। इतिहास की

श्रीलंका: पहले मौके पर गिराएंगे सरकार

कोलंबो। श्रीलंका में सरकार और विपक्षी दल के बीच जारी तनाव के बीच पूर्व राष्ट्रपति महिदा राजपक्ष के नेतृत्व वाले विपक्षी दल ने राष्ट्रीय जनशक्ति (एनपीपी) सरकार पर चुनावी वादों को पूरा ना करने का आरोप लगाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो पहले मौके पर सरकार को गिरा दिया जाएगा। राजधानी कोलंबो के उपनगर नुगेगोडा में शुक्रवार को आयोजित एक रैली में महिदा राजपक्ष के बेटे और राजनीतिक उत्तराधिकारी नमल राजपक्ष ने कहा कि हम तैयार हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि हम पहले मौके पर इस गिरा देंगे। नमल ने आगे कहा कि श्रीलंकाई सरकार को जनता से किए गए अपने वादे पूरे करने चाहिए। इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल या जमानत पर कई पार्टी नेताओं को बाबजूद वध डरंगे नहीं और संघर्ष जारी रखेंगे। बता दें कि श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ आयोजित रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, हालांकि मुख्य विपक्षी दल एसजेबी ने इसमें भाग नहीं लिया।

यौन समस्याएं

यौन समस्याओं के विशेषज्ञ

पुराने से पुराने यौन रोग के मरीज एक बार अवश्य मिलें

डा. सम्राट

नशामुक्ति, शराब, बीडी, सिगरेट, गुटखा तम्बाकू, प्रोक्सीवॉन के प्रसूत अपीम, चरस, डोड पोस्ट हंजेक्शन व अन्य नशा छुड़ाने का स्थायी ईलाज।

नावल्टी सिनेमा चौक मुजफ्फरनगर (यू.पी.)

M-9412211108